



भारत का राजपत्र The Gazette of India

CK
11/8/85

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 1985/चैत्र 6, 1907
No. 136] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1985/CHAITRA 6, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1985

सा. का. नि. 315(अ) :—नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियों तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति

ने नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, नियंत्रक-महा-लेखा परीक्षक को एतद् द्वारा संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के खातों को रखने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है।

2. यह आदेश पहली अप्रैल, 1985 से प्रवृत्त होगा।

[संख्या एफ. 1(7)-बी (ए. सी.)/85]

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम से
ए. रंगाचारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 27th March, 1985

G.S.R. 315(E).—In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 10 of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971), the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General, hereby relieves the Comptroller and Auditor General from the responsibility of keeping the General Provident Fund Accounts of all employees of the Government of the Union territory of Arunachal Pradesh.

2. This order shall come into force with effect from 1st April, 1985.

[No. F. 1(7)-B(AC)|85]

By order and in the name of the President.

A. RANGACHARI, Jt. Secy.